

चलनधिसमायोजन सुवधि

प्रलिस के लयि:

चलनधि (तरलता) समायोजन सुवधि (LAF), ढौदरकि नीति, नरसहिम समति

ढेन्स के लयि:

चलनधिसमायोजन सुवधि (LAF)

चरचा में क्यौं?

भरतीय रजिर्व बैंक (RBI) ने अकतूबर 2022 में बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ावा देने के लयि 72,860.7 करोड़ रुपए का नविश कयि। तयोहारी सीजन के दौरान क्रेडिट की अधकि ढांग के चलते तरलता की स्थिति सिखत होने के बाद यह अप्रैल 2019 के बाद से सबसे अधकि है।

- रुपए की अस्थरिता को कम करने के लयि यह वदिशी ढुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक का हस्तकषेप है।

तरलता:

- बैंकिंग प्रणाली में तरलता **आसानी से उपलब्ध नकदी** को संदरभति करती है जिससे बैंक अल्पकालकि वयापार और वत्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं।
- किसी नशिचति दनि पर यद बैंकिंग प्रणाली **तरलता समायोजन सुवधि (LAF)** के तहत RBI से एक शुद्ध उधारकरत्ता है, तो इसे तरलता के घाटे की स्थिति कहा जाता है और यद बैंकिंग प्रणाली RBI के लयि एक शुद्ध ऋणदाता है तो इसे तरलता अधशिष कहा जाता है।

तरलता समायोजन सुवधि (LAF):

- LAF भरतीय रजिर्व बैंक की **ढौदरकि नीति** के तहत प्रयोग कयि जाने वाला उपकरण है जो बैंकों को पुनरखरीद समझौतों, रेपो एग्रीमेंट के ढाध्यम से ऋण प्राप्त करने या रविर्स रेपो एग्रीमेंट के ढाध्यम से RBI को ऋण प्रदान करने की अनुढति प्रदान करता है।
- इसे वर्ष 1998 के बैंकिंग कषेत्र सुधारों पर **नरसहिम समति** के परिणाम के एक ढाग के रूप में पेश कयि गया था।
- तरलता समायोजन सुवधि के दो घटक रेपो (पुनरखरीद समझौता) और रविर्स रेपो हैं।** जब बैंकों को अपनी दैनकि आवश्यकता को पूरा करने के लयि तरलता की आवश्यकता होती है, तो वे रेपो के ढाध्यम से RBI से उधार लेते हैं। जब बैंकों के पास धन की अधकिता होती है, तो वे रविर्स रेपो प्रणाली के ढाध्यम से रविर्स रेपो दर पर RBI को उधार देते हैं।
- इससे ढुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर व घटाकर **अर्थव्यवस्था में ढुद्रासफीता** का प्रबंधन कयि जा सकता है।
- LAF का उपयोग बैंकों को आर्थकि अस्थरिता की अवधि के दौरान या उनके नयितरण से परे होने वाले उतार-चढ़ाव की स्थिति में **अल्पकालकि नकदी की कमी को पूरा करने के लयि** कयि जाता है।
- वभिन्नि बैंक रेपो समझौते के ढाध्यम से पात्र प्रतभूतयिों को बंधक के रूप में उपयोग करते हैं और अपनी अल्पकालकि आवश्यकताओं को पूरा करने के लयि धन का उपयोग करते हैं, इस प्रकार इनकी स्थरिता बनी रहती है।
- इस सुवधि को दनि-प्रतदिनि के आधार पर लागू कयि जाता है क्यौंकि बैंक और अन्य वत्तीय संस्थान सुनशिचति करते हैं कि उनके पास ओवरनाइट बाजार में परयाप्त पूंजी है।
- चलनधिसमायोजन सुवधिओं का लेन-देन **नीलामी के ढाध्यम से** दनि के एक नरिधारति समय पर होता है।

ढौदरकि नीति:

- ढौदरकि नीति का तात्पर्य नरिदषिट लकष्यों को प्राप्त करने के लयि **केंद्रीय बैंक द्वारा अपने नयितरण में ढौदरकि साधनों** का उपयोग करना है।
- RBI की ढौदरकि नीति का प्रथमकि उद्देश्य, वकिस को ध्यान में रखते हुए ढूल्य स्थरिता बनाए रखना है।
 - सतत् वकिस के लयि ढूल्य स्थरिता एक आवश्यक पूर्व शर्त है।
- संशोधति RBI अधनियिढ, 1934 में हर पाँच साल में एक बार रजिर्व बैंक के परामरश से भरत सरकार द्वारा नरिधारति **ढुद्रासफीता लकष्य (4% +**

-2%) रखने का भी प्रावधान है।

- मौद्रिक नीति के उपकरण:
 - नकद आरक्षति अनुपात (CRR)।
 - वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)।
 - बैंक दर।
 - स्थायी जमा सुवधि (SDF)।
 - सीमांत स्थायी सुवधि (MSF)।
 - नकद आरक्षति अनुपात (CRR)।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. यदि भारतीय रज़िर्व बैंक एक वसितारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का नरिणय लेता है, तो वह नमिनलखिति में से क्या नहीं करेगा? (2020)

1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन
2. सीमांत स्थायी सुवधि दर में बढ़ोतरी
3. बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- वसितारति मौद्रिक नीति आसान मौद्रिक नीति उसे कहते हैं जब केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिये अपने उपकरणों का उपयोग करता है। यह मुद्रा आपूर्ति तथा मांग को बढ़ाता है, ब्याज दरों को कम करता है, इस प्रकार यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
- वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI), बैंकों के नपिटान में तरलता का आकलन करने के लिये करता है। यह जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंक को नकद, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। यह मूल रूप से आरक्षति आवश्यकता है जिसे बैंकों से ग्राहकों को ऋण देने से पहले रखने की अपेक्षा की जाती है। एसएलआर बढ़ाने से बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक पैसा लगाते हैं और अर्थव्यवस्था में नकदी के स्तर को कम करते हैं। इसकी विपरीत स्थिति में अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलती है। एसएलआर कम करने से बैंकों के पास अधिक तरलता बच जाती है जो बदले में अर्थव्यवस्था में विकास और मांग को बढ़ावा दे सकती है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- सीमांत स्थायी सुवधि (Marginal Standing Facility- MSF): वह सुवधि जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने 'वैधानिक तरलता अनुपात' (SLR) पोर्टफोलियो में नशिचति सीमा तक कमी (Dipping) करके ओवरनाइट सुवधि के तहत अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। एमएसएफ दर में वृद्धि के साथ बैंकों को उधार लेने की लागत बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप उधार देने के लिये उपलब्ध संसाधन कम हो जाते हैं। अतः कथन 2 सही है।
- रेपो दर या पुनर्खरीद दर ब्याज की प्रमुख मौद्रिक नीति दर है जिस पर केंद्रीय बैंक या भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) तरलता समायोजन सुवधि (LAF) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के बदले बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। बैंक दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने दीर्घकालिक ऋणों पर वसूल करता है। वसितारवादी मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिये रेपो दर एवं बैंक दर को कम करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

प्रश्न: क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि स्थिर GDP वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति प्रदान की है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2019)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)